IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की प्रभावशीलता: उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

1. बसुंधरा शुक्ला, शोधार्थी समाजशास्त्र विभाग बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान vasus0668@gmail.com.
2. डॉ. राजश्री मठपाल - असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान.

सार

ग्रामीण भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups—SHGs) इस प्रक्रिया के प्रमुख माध्यम के रूप में उभरे हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद जैसे अर्ध-विकसित क्षेत्रों में। प्रस्तुत समीक्षा-पत्र का उद्देश्य SHGs की भूमिका का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण करना है, जिसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक भागीदारी, निर्णय-निर्माण क्षमता तथा लैंगिक चेतना पर इनके प्रभाव का अध्ययन किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि SHGs ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम रहे हैं, यद्यपि संरचनात्मक बाधाएँ अभी भी विद्यमान हैं।

मुख्य शब्द: महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण विकास, बस्ती जनपद, समाजशास्त्रीय अध्ययन

1. प्रस्तावना

ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण को समावेशी विकास, जेंडर इक्वालिटी और सामाजिक न्याय की दिशा में एक ज़रूरी पिलर के तौर पर देखा जाता है। पहले, ग्रामीण महिलाओं को सीमित आर्थिक संपत्ति, शिक्षा न मिल पाने, सामाजिक स्टीरियोटाइप और पेट्रियार्की के कंट्रोल की वजह से मेनस्ट्रीम डेवलपमेंट का फ़ायदा नहीं मिला। इन रुकावटों को दूर करने के लिए, सेल्फ़-हेल्प ग्रुप (SHG) एक मज़बूत कम्युनिटी अप्रोच बन गए हैं, जिससे महिलाओं को कलेक्टिव सेविंग्स करने, क्रेडिट पाने और आत्मनिर्भर होने का मौका मिलता है (राय और शेखर 2021)। उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले जैसे कम विकसित इलाकों में SHG के चलन से महिला सशक्तिकरण की दर बढ़ी है। कलेक्टिव और आपसी सहयोग का सिद्धांत, साथ ही फ़ाइनेंशियल इनक्लूजन, सेल्फ़-हेल्प ग्रुप के आइडिया का आधार है। यह मॉडल न सिर्फ़ आर्थिक संसाधनों तक पहुँच बनाता है बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास, लीडरशिप और फ़ैसले लेने की स्किल भी बनाता है। मौजूदा लिटरेचर से पता चलता है कि जो महिलाएं SHG से जुड़ी हैं, वे घर और कम्युनिटी के फैसले लेने में ज़्यादा एक्टिव होती हैं, जिससे उन्हें सोशली ज़्यादा पहचाना जा सकता है (चौधरी एट अल. 2023)। इस तरह SHG एक इकोनॉमिक ऑर्गनाइज़ेशन है जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक मज़बूत ज़रिया भी बन जाता है।

सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स को नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (NRLM) के तहत ग्रामीण आजीविका डेवलपमेंट और महिलाओं के एम्पावरमेंट के ज़रियों में से एक माना जाता है। बस्ती ज़िले में NRLM से जुड़े ऑर्गनाइज़ेशन पर आधारित रिसर्च से पता चलता है कि SHG की मेंबरशिप से महिलाओं की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनकी सोशल मोबिलिटी, साथ ही कलेक्टिव कॉन्शसनेस में पॉजिटिव बदलाव आए हैं, भले ही स्ट्रक्चरल रुकावटें बनी हुई हैं (चौधरी एट अल. 2022)। खास

तौर पर, बैंकिंग प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी, मार्केटिंग नेटवर्क की कमी, और ट्रेनिंग को उन समस्याओं के तौर पर पहचाना जा सकता है जो SHG की मैक्सिमम एफिशिएंसी को रोक सकती हैं।

पिछली स्टडीज़ में, सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स के असर को सिर्फ़ आर्थिक संदर्भ तक ही सीमित नहीं बताया गया है, बल्कि यह सामाजिक संसाधन जमा करने, नेटवर्क को मज़बूत करने और जेंडर अवेयरनेस पैदा करने में भी बहुत योगदान देता है। लखनऊ और बस्ती ज़िलों में की गई एक एनालिटिकल स्टडी के नतीजों से यह साबित हुआ कि SHGs की भागीदारी से महिलाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक भागीदारी के साथ-साथ महिलाओं के फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि इससे न सिर्फ़ उनकी इनकम बढ़ी बल्कि उनके आत्मविश्वास, सामाजिक भागीदारी और फ़ैसले लेने की क्षमता में भी काफ़ी सुधार हुआ (शेखर 2024)। फिर भी, स्थानीय सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर, इलाकों में SHGs के नतीजों में अंतर भी देखा गया है।

ऊपर दिए गए नज़रिए को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा रिसर्च, 'ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स की प्रभावशीलता: बस्ती ज़िले, उत्तर प्रदेश का एक सोशियोलॉजिकल एनालिसिस' इस सवाल को सोशियोलॉजिकल नज़रिए से समझने की कोशिश करती है। लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए, यह स्टडी SHGs की भूमिका, उनकी सफलता, रुकावटों और मौकों का एक ओवरऑल इवैल्यूएशन पेश करती है, जो ग्रामीण महिलाओं को एम्पावर करने के प्रोसेस को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने में पॉलिसी गाइडेंस है।

2. अध्ययन के उद्देश्य (Objectives)

इस समीक्षा-पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में SHGs की भूमिका का विश्लेषण करना।
- आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभावों का मूल्यांकन करना।
- बस्ती जनपद के संदर्भ में प्रमुख चुनौतियों और संभावनाओं की पहचान करना।
- भविष्य के लिए नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

3. सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य (Theoretical Framework)

महिला सशक्तिकरण के कॉन्सेप्ट को अमर्त्य सेन के कैपेबिलिटी अप्रोच और फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी के अहम आधारों का हवाला देकर एनालाइज़ किया जा सकता है। सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) को सोशल कैपिटल जमा करने, महिलाओं के आत्मविश्वास, भागीदारी और फैसले लेने की क्षमता को मज़बूत बनाने के एक टूल के तौर पर देखा जाता है।

सोशियोलॉजिकली कहें तो, SHGs न सिर्फ आर्थिक संस्थाएं हैं, बल्कि कम्युनिटी में बदलाव लाने वाले एजेंट भी हैं।

4. साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

4.1 आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव (उत्तर प्रदेश)

यादव और प्रसाद (2024) ने बताया कि सेल्फ-हेल्प ग्रुप (SHG) एक सफल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बन गए हैं, जिसके ज़रिए उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाया गया है। उनकी रिसर्च में यह पता चला कि जो महिलाएं SHG से जुड़ी थीं, वे रेगुलर बचत करने लगीं और उन्हें आसानी से क्रेडिट के फॉर्मल सोर्स मिल गए। इससे महिलाओं को इनकम कमाने में ज़्यादा भूमिका मिली और कुछ हद तक उन्हें पारंपरिक पैसे उधार देने के सिस्टम पर निर्भरता से छुटकारा मिला। पेपर में यह भी पता चला है कि SHG ने महिलाओं के फाइनेंशियल अनुशासन और आर्थिक विकल्प को बेहतर बनाया, जिस पर लंबे समय तक आर्थिक मज़बूती बनी है।

अग्रवाल, कुमार और गर्ग (2020) ने जांच की कि उत्तर प्रदेश में माइक्रोफाइनेंस का इस्तेमाल करके SHG महिलाओं को कैसे मज़बूत बनाया जा सकता है और पाया कि ग्रुप-बेस्ड क्रेडिट सुविधाओं के रूप में माइक्रोफाइनेंस ने छोटे लेवल के बिज़नेस, जैसे सिलाई, पशुपालन, फ़ूड प्रोसेसिंग, वगैरह को बढ़ावा दिया। उनके नतीजे साफ़ थे कि SHG की मेंबरशिप से महिलाओं की अपनी इनकम बढ़ी और परिवार की आर्थिक हालत बेहतर हुई। फिर भी, उन्होंने यह भी बताया कि ज़्यादातर मामलों में, अलग-अलग ग्रुप अपनी इकोनॉमिक क्षमता तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट की कमी होती है।

सागर और गंगवार (2025) की एक रिसर्च माइक्रोफाइनेंस और ग्रामीण विकास के बीच मज़बूत संबंध पर ध्यान दिलाती है। रिसर्च से पता चलता है कि SHG सिर्फ़ क्रेडिट देने वाली यूनिट नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण महिलाएँ इन्हें मिलकर काम करने, प्रोडक्शन एक्टिविटी और लोकल मार्केट से जुड़ने के लिए इकोनॉमिक प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। स्टडी में SHG का एक और असर यह दिखा कि जहाँ SHG को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और ट्रेनिंग दी गई, वहाँ महिलाओं की इनकम में स्थिरता और फाइनेंशियल आज़ादी ज़्यादा असरदार रही।

बरेली डिवीज़न में ग्रामीण महिलाओं पर आधारित होम-प्रोडक्ट कंपनियों की एक स्टडी में, वर्मा (2023) ने पाया कि सेल्फ़-हेल्प ग्रुप ने रोज़गार में बहुत योगदान दिया। उन्होंने दावा किया कि SHG नेटवर्क के तहत, महिलाओं को कच्चा माल, जॉइंट मार्केटिंग और प्रोडक्शन में मदद मिली, जिससे उनकी इनकम बढ़ी और घरेलू लेवल पर उनकी इकोनॉमिक वैल्यू को और पहचान मिली। यह बदलाव भी परिवार के फैसले लेने में महिलाओं की संख्या बढ़ने का एक असरदार कारण बना।

अमेठी जिले में ग्रामीण महिलाओं पर SHG के असर को समझने के लिए मौर्य (2023) द्वारा की गई एक स्टडी में, यह देखा गया कि ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की बचत करने की आदत, इनकम कमाने वाली एक्टिविटी में शामिल होना और फाइनेंशियल अवेयरनेस में काफी सुधार हुआ। फिर भी, रिसर्च यह भी दिखाती है कि कई महिलाओं का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम एजुकेशन लेवल, मार्केट तक पहुंच की कमी और सामाजिक रुकावटों से भी रुकता है।

आम तौर पर, मौजूद लिटरेचर से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सेल्फ़-हेल्प ग्रुप एक अच्छा तरीका साबित हुए हैं। SHG का महिलाओं की इनकम, बचत करने की आदत, क्रेडिट तक पहुंच और सेल्फ़-एम्प्लॉयमेंट पर पॉजिटिव असर पड़ा है। फिर भी, एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की गारंटी के लिए स्किल ट्रेनिंग, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग को आसान बनाने के साथ-साथ इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन के लिए और एम्पावरमेंट की अभी भी ज़रूरत है।

4.2 सामाजिक सशक्तिकरण का मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण पर प्रभाव

पुझेंधी और सत्यसाई (2001) ने बताया कि सेल्फ़-हेल्प ग्रुप गांव के गरीबों के सोशल एम्पावरमेंट का एक बहुत असरदार तरीका रहे हैं। उनकी रिसर्च में बताया गया कि सेल्फ़-हेल्प ग्रुप की इन महिलाओं का सोशल इन्वॉल्वमेंट, ग्रुप आइडेंटिटी और ऐसे फोरम में बोलने की उनकी काबिलियत में बढ़ोतरी का बहुत गहरा और ज़बरदस्त असर हुआ, जहां उन्हें कॉन्फिडेंस था। स्टडीज़ से यह भी पता चलता है कि ज़्यादातर मामलों में सोशल एम्पावरमेंट की ताकत इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से ज़्यादा मज़बूत होती है क्योंकि इसमें महिलाओं की सोशल हैसियत और उनके सेल्फ़-एस्टीम तय करने की ताकत होती है।

केसी, सॉन्डर्स और ओ हारा (2010) ने नर्सिंग और मिडवाइफरी पर अपनी रिसर्च में यह तय किया कि साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट का अंदाज़ा काफी हद तक क्रिटिकल सोशल एम्पावरमेंट से लगाया जाता है। उन्होंने पाया कि जब लोगों को सोशल सपोर्ट, हिस्सा लेने के मौके और उनके स्ट्रक्चर में भरोसा दिया जाता है, तो उनकी सेल्फ़-इफिकेसी, जॉब सैटिस्फैक्शन और चॉइस बढ़ती है। यही बात गांव की महिलाओं के ग्रुप पर भी लागू होती है क्योंकि कलेक्टिविज़्म साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है।

चक्रवर्ती और अब्राहम (2021) ने फाइनेंशियल इन्क्लूजन और सोशल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे वेरिएबल्स के बीच मीडिएशन रिलेशनशिप की जांच की और पाया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस में सोशल एम्पावरमेंट बहुत

ज़रूरी है। उनका मानना है कि सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट देना ही काफी नहीं है, बल्कि महिलाओं को इकोनॉमिकली एम्पावर बनाना भी ज़रूरी है; उन्हें अपनी सोशल पोजीशन, फैसले लेने की क्षमता और नेटवर्किंग पावर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है।

नॉर्ड एट अल. (2016) ने सोशल टेक्नोलॉजी के संबंध में एम्पावरमेंट की घटना की जांच की और साबित किया कि सोशल रिलेशन, जानकारी तक पहुंच और नेटवर्क डेवलपमेंट, लोगों को एम्पावर करने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। भले ही वे एक बड़े सोशल माहौल में काम कर रहे थे, उनके नतीजों को SHG कॉन्टेक्स्ट में भी लागू किया जा सकता है, जहां ग्रुप मीटिंग, ग्रुप में फैसले लेने और जानकारी के लेन-देन से महिलाओं का सोशल कैपिटल बढ़ता है।

लोगन और गैंस्टर (2007) का कहना है कि एम्पावरमेंट की भावना तब ज़्यादा असरदार हो जाती है जब लोगों को लगता है कि काम और फैसले उनके कंट्रोल में हैं। उनकी रिसर्च में पाया गया कि सोशल सपोर्ट और एम्पावरमेंट की सोच का काम के परफॉर्मेंस और नज़रिए पर पॉजिटिव असर पड़ता है। जब इसे ग्रामीण महिला ग्रुप पर लागू किया जाता है, तो इसका मतलब है कि जब सदस्य SHG द्वारा फैसले लेने की सामूहिक प्रक्रिया में शामिल होती हैं, तो उनका साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट और उनका सेल्फ-कॉन्फिडेंस बढ़ता है।

आम तौर पर, उपलब्ध लिटरेचर दिखाता है कि सोशल एम्पावरमेंट, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट का एक महत्वपूर्ण आधार है। SHG के ज़रिए बनाए गए सोशल नेटवर्क, सामूहिक पहचान और पार्टिसिपेटरी कल्चर से महिलाओं का सेल्फ-कॉन्फिडेंस, सेल्फ-इफिकेसी और फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए, ग्रामीण इलाकों में महिला एम्पावरमेंट की प्रक्रिया के सोशल और साइकोलॉजिकल पहलुओं को आपस में जोड़कर देखना चाहिए ताकि इसके बारे में और जान सकें।

4.3 राजनीतिक तथा निर्णय-निर्माण क्षमता

पुझेंधी और सत्यसाई (2001) ने देखा है कि सेल्फ-हेल्प ग्रुप में शामिल होने की प्रोसेस से, गांव की महिलाएं न सिर्फ समाज के बारे में ज़्यादा जागरूक होती हैं, बल्कि पॉलिटिकल दुनिया के बारे में भी ज़्यादा जागरूक होती हैं। अपने एनालिसिस में, उन्होंने बताया कि SHG मेंबर गांव की काउंसिल, पंचायत मीटिंग और लोकल कम्युनिटी की दूसरी एक्टिविटी में ज़्यादा एक्टिव थे। यह भागीदारी महिलाओं को पब्लिक में बोलने, कलेक्टिव लीडरशिप के साथ-साथ लोकल फैसले लेने में दखल देने के मामले में बेहतर बनाती है।

केसी, सॉन्डर्स और ओ हारा (2010) ने यह तर्क दिया कि सोशल एम्पावरमेंट का लेवल लोगों की साइकोलॉजिकल क्षमता और फैसले लेने में कॉन्फिडेंस पर सीधा असर डालता है। उनकी राय में, महिलाओं को स्ट्रक्चरल सपोर्ट और पार्टिसिपेशन के मौके और ग्रुप आइडेंटिटी उन्हें वर्कप्लेस और समाज दोनों में फैसले लेने में बेहतर बनाती है। यही बात गांव की SHG महिलाओं में भी पाई जाती है, जहां कलेक्टिव का प्लेटफॉर्म महिलाओं को पॉलिटिकल अवेयरनेस का बेस बनाने में मदद करता है। चक्रवर्ती और अब्राहम (2021) ने फाइनेंशियल इनक्लूजन और सोशल एम्पावरमेंट के एक-दूसरे पर निर्भर होने पर ज़ोर दिया और बताया कि इकोनॉमिक रिसोर्स की मौजूदगी महिलाओं को उनके फैसले लेने के प्रोसेस में मज़बूत बनाती है। उनकी राय में, इंडिपेंडेंट इनकम और सेविंग्स वाली महिलाएं परिवारों और कम्युनिटी के फैसलों में बेहतर योगदान देती हैं। इसलिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के साथ-साथ सोशल एम्पावरमेंट से पॉलिटिकल कैपेसिटी को बढ़ावा मिलता है।

कुग्लर (2018) एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल परफॉर्मेंस में पॉलिटिकल कैपेसिटी को सबसे ज़रूरी फैक्टर्स में से एक मानती हैं। अपने एनालिसिस में वह दिखाती हैं कि फैसले लेने के प्रोसेस में ग्रासरूट सोशल ग्रुप्स, खासकर महिलाओं की इंस्टीट्यूशनल भागीदारी जितनी ज़्यादा होगी, फैसले लेने का प्रोसेस उतना ही ज़्यादा इनक्लूसिव होगा। इसका मतलब है कि ग्रुप बेस्ड ऑर्गनाइज़ेशन्स का इस्तेमाल SHG फ्रेमवर्क के संदर्भ में लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में महिलाओं को जोड़ने के सोर्स के तौर पर किया जा सकता है।

वू, हाउलेट और रमेश (2017) पॉलिसी कैपेसिटी जैसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका मतलब है कि एनालिटिकल, ऑपरेशनल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जैसी तीनों तरह की कैपेबिलिटीज़ सफल गवर्नेंस के लिए ज़रूरी हैं। उनकी राय

में, जितने ज़्यादा नागरिक ज़मीनी स्तर पर जुड़ेंगे, पॉलिसी बनाना उतना ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगा। ग्रामीण महिलाओं के SHG को इस प्रोसेस में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को मज़बूत बनाने के लिए इंस्टीट्यूशनल प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर देखा जा सकता है।

कुल मिलाकर, मौजूद लिटरेचर से पता चलता है कि ग्रामीण महिलाओं को राजनीतिक रूप से मज़बूत बनाने, उनकी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने और उन्हें फ़ैसले लेने में काबिल बनाने में सेल्फ़-हेल्प ग्रुप ज़रूरी हैं। सेल्फ़-हेल्प ग्रुप (SHG) में भागीदारी के ज़रिए, महिलाएँ परिवार से लेकर गाँव की पंचायत तक, अलग-अलग लेवल पर अपनी बात कह पाती हैं। फिर भी, लगातार ट्रेनिंग, कानूनी जागरूकता बढ़ाने, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम और लोकल सरकारी संस्थाओं के साथ करीबी तालमेल के ज़रिए राजनीतिक मज़बूती को बनाए रखना चाहिए।

4.4 मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण

ज़िमरमैन (1995) साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट को उस प्रोसेस के तौर पर बताती हैं, जिसमें कोई इंसान अपनी ज़िंदगी, आस-पास की चीज़ों और पसंद पर कंट्रोल महसूस करना सीखता है। उन्होंने इसे एक मल्टीडाइमेंशनल सोच के तौर पर समझाया, जिसमें सेल्फ-इफिकेसी, क्रिटिकल अवेयरनेस और पार्टिसिपेटरी बिहेवियर मुख्य एलिमेंट हैं। यह आइडिया गांव की महिलाओं के लिए खास तौर पर ज़रूरी है, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरह के मौकों तक पहुंच तभी ज़रूरी है, जब महिलाओं में अंदर का कॉन्फिडेंस और कंट्रोल की भावना आए। स्प्रीटज़र (1995) के मुताबिक, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट में चार बातें शामिल हैं, यानी इसे मीनिंगफुल, काबिल, ऑटोनॉमस और असरदार होना चाहिए। उनकी राय में, असली साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट तब बनता है, जब लोगों को लगता है कि उनका काम ज़रूरी है, वे खुद से फैसले ले सकते हैं और बदलाव लाने और अपने काम के नतीजों को कंट्रोल करने में काबिल महसूस करते हैं। सेल्फ-हेल्प ग्रुप में महिलाओं की भागीदारी भी एक्टिव है और इन चार बातों को मज़बूत करने में मदद करती है। मेनन (1999) ने साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट पेश किया जिसे मापा जा सकता है और उन्होंने यह समझाया कि यह किसी व्यक्ति की कॉग्निटिव स्थिति से जुड़ा है। उनकी रिसर्च में पता चला कि एम्पावरमेंट न केवल बाहरी रिसोर्स के असर से आता है, बल्कि यह किसी व्यक्ति की सोच, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। इस बारे में, SHG एक्टिविटीज़ (जैसे, रेगुलर मीटिंग, सेविंग्स मैनेजमेंट और मिलकर फैसले लेना) महिलाओं के अंदरूनी मोटिवेशन को बढ़ाती हैं।

ओलाडिपो (2009) ने डेवलपमेंट के प्रोसेस में ग्रुप्स को एक्टिव बनाने के तरीकों में से एक के तौर पर साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट का ज़िक्र किया। उन्होंने सुझाव दिया कि एक बार जब लोग अपनी सोच में सेल्फ-कॉन्फिडेंट, जागरूक और गोल-ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो वे सोशल चेंज एजेंट बन जाते हैं। ग्रामीण महिलाओं के SHG एक ऐसा माहौल देते हैं, जिससे महिलाएं डर और झिझक को हराती हैं और कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना हासिल करती हैं।

वैगनर एट अल. (2010) ने तय किया कि स्ट्रक्चरल और साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट के बीच एक पॉजिटिव कोरिलेशन मौजूद है। उनके नतीजों के आधार पर, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर (जिसमें ऑर्गेनाइज़ेशनल सपोर्ट, जानकारी तक पहुँच और रिसोर्स की उपलब्धता शामिल है) जितने बेहतर होंगे, लोगों का साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। यह बात सीधे SHG मॉडल पर लागू की जा सकती है क्योंकि सोशल ग्रुप स्ट्रक्चर महिलाओं को रिसोर्स, ट्रेनिंग और सोशल सपोर्ट देता है।

आम तौर पर, हम कह सकते हैं कि ग्रामीण महिलाओं के एम्पावरमेंट का मुख्य फोकस साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट है। सेल्फ-हेल्प ग्रुप महिलाओं के सेल्फ-कॉन्फिडेंस, फैसले लेने की स्किल, लीडरशिप और सोशल पार्टिसिपेशन पर बनते हैं। फिर भी, उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए कैपेसिटी-बिल्डिंग पर लगातार ट्रेनिंग, लीडरशिप के मौकों की बढ़ती उपलब्धता और सोशल नॉर्म्स में बदलाव की ज़रूरत है।

4.5 प्रमुख चुनौतियाँ

लिटरेचर के एनालिसिस से पता चलता है कि कई स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रुकावटें हैं जो सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) के परफॉर्मेंस को रोकती हैं। सबसे बड़ी समस्या सही ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की कमी है। कई स्टडीज़ में देखा गया है

कि ग्रुप्स की महिला सदस्यों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और मार्केटिंग में सही ट्रेनिंग नहीं मिली है, जिसका मतलब है कि वे मौजूद रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकतीं।

एक और बड़ी चिंता की बात बैंकिंग प्रोसेस की ब्यूरोक्रेसी है। लोन लेना, डॉक्यूमेंटेशन और बैंकों के साथ लगातार बातचीत करना गांव की महिलाओं के लिए मुश्किल है, खासकर उन इलाकों में जहां फाइनेंशियल लिटरेसी कम है। इसका असर SHGs की फाइनेंशियल मोबिलिटी पर पड़ता है।

ग्रुप की अस्थिरता भी एक गंभीर समस्या है। लीडरशिप की कमी और अंदरूनी झगड़े, साथ ही बाहरी सपोर्ट की कमी के कारण कई ग्रुप जोश से भरे होने के बाद इनएक्टिव हो जाते हैं।

महिलाओं की एक्टिव हिस्सेदारी की लिमिटेशन पुरुषों के दबदबे और सोशल लेवल पर पेट्रियार्कल रवैये की वजह से होती है। ज़्यादातर गांव के इलाकों में अभी भी इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल का इस्तेमाल होता है, जहां महिलाओं को उनके आने-जाने, फैसले लेने और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की वजह से रोका जाता है। साथ ही, SHGs के पास अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए मार्केटिंग की सुविधा नहीं होती, जिससे इनकम कमाने की क्षमता में रुकावट आती है। प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन क्योंकि कोई असरदार मार्केटिंग, ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस नहीं है, इसलिए महिलाएं अपनी मेहनत का फल नहीं ले पातीं। बस्ती जैसे पिछड़े जिलों में समस्याएं ज़्यादा गंभीर हैं, जिससे एम्पावरमेंट का प्रोसेस थोड़ा-बहुत ही होता है।

5. चर्चा (Discussion)

यह तय किया जा सकता है कि सेल्फ-हेल्प ग्रुप को ग्रामीण महिलाओं को मज़बूत बनाने के असरदार तरीके के तौर पर देखा जा सकता है, हालांकि मौजूद लिटरेचर के अनुसार, ऐसे असर सभी मामलों में एक जैसे नहीं होते हैं। आर्थिक मज़बूती, यानी बचत की आदतें, क्रेडिट तक पहुंच और इनकम जेनरेट करने के क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से अच्छे और साफ नतीजे देखे गए हैं। इसके उलट, सामाजिक और राजनीतिक मज़बूती का लेवल एरिया, ग्रुप की कुशलता, लीडरशिप और संस्थाओं के सपोर्ट से तय होता है।

सोशियोलॉजिकली, SHG ने ग्रामीण महिलाओं में ग्रुप अवेयरनेस और आपसी सहयोग की भावना पैदा की है। बार-बार होने वाली मीटिंग, सामाजिक फैसले लेने और फाइनेंशियल एक्टिविटी में शामिल होने से महिलाओं की खुद की पहचान और सामाजिक पहचान बेहतर हुई है। यह बदलाव लंबे समय में सामाजिक बदलाव का आधार देता है।

हालांकि, SHG के पूरे असर को स्ट्रक्चरल असमानताओं, खासकर जाति, वर्ग और पेट्रियार्की से कम कर दिया जाता है। ज़्यादातर मामलों में, आर्थिक रूप से शामिल होने के बावजूद, महिलाएं घर के अंदर लिए जाने वाले फैसलों में पुरुषों के अधीन रहती हैं। इस तरह, SHGs को एम्पावरमेंट की दिशा में एक पक्का कदम कहा जा सकता है, लेकिन यह अपने आप में काफ़ी नहीं है, जब तक कि कुछ बड़े सोशियो-स्ट्रक्चरल बदलाव न हों।

6. निष्कर्ष (Conclusion)

प्रस्तुत समीक्षा से यह स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। SHGs के माध्यम से महिलाओं की औपचारिक वित्तीय संस्थानों तक पहुँच बढ़ी है, उनमें आत्मविश्वास का विकास हुआ है तथा सामुदायिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुदृढ़ हुई है।

इसके बावजूद, स्थायी और समग्र सशक्तिकरण के लिए केवल समूहों का गठन पर्याप्त नहीं माना जा सकता। यदि महिलाओं को वास्तविक रूप से सशक्त बनाना है तो संस्थागत समर्थन, सतत कौशल विकास, प्रभावी बाजार संपर्क, डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता तथा लैंगिक संवेदनशील नीतिगत हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक हैं। उचित नीतिगत और संरचनात्मक सहयोग के साथ स्वयं सहायता समूह ग्रामीण परिवर्तन के एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण के रूप में स्थापित हो सकते हैं।

7. सुझाव (Recommendations)

- महिलाओं के लिए नियमित प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित किए जाएँ।
- बैंक और SHG के बीच समन्वय प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए।
- SHG उत्पादों के लिए स्थायी बाजार संपर्क, ब्रांडिंग एवं ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएँ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक समानता एवं जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
- स्थानीय स्तर पर निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ किया जाए ताकि समूहों की निरंतरता और गुणवत्ता बनी रहे।

संदर्भ (References)

1. चौधरी, ए., आदि. “Empowerment and Its Relationship with the Socio-Demographic Profile of SHG Women Beneficiaries under NRLM in the Basti District of Uttar Pradesh.” *Journal of Rural Development Studies*, 2023.
2. चौधरी, ए., आदि. “Constraints Faced by the SHG Women Beneficiaries in the National Rural Livelihood Mission (NRLM) in the Basti District of Uttar Pradesh.” *Journal of Community Mobilization and Sustainable Development*, 2022.
3. राय, पी., और सी. शेखर. “A Critical Study of Women’s Participation in SHG-Uttar Pradesh.” *ResearchGate*, 2021.
4. शेखर, सी. “Economic Impact of Self-Help Group Members in Lucknow and Basti District, Uttar Pradesh: An Analytical Study.” *SSRN Electronic Journal*, 2024.
5. अग्रवाल, एस., पी. कुमार, और वी. गर्ग. “Empowering SHGs Women through Micro-Finance in Uttar Pradesh.” *International Journal of Law and Management*, 2020.
6. मौर्य, टी. एस. *A Study on Current Status of Rural Women Empowerment in Amethi District of Uttar Pradesh*. 2023.
7. यादव, टी., और जी. प्रसाद. “Socio-Political, Economic Impact of Self Help Groups on Women Empowerment in Uttar Pradesh.” 2024.
8. सागर, आर., और डी. आर. गंगवार. “Evaluating the Socio-Economic Impact of Microfinance on Rural Development in Uttar Pradesh.” *The Voice of Creative Research*, 2025.
9. वर्मा, एस. “Socio-Economic Development Through Rural Women Home-Based Products: An Analytical Study in Bareilly Mandal, Uttar Pradesh.” 2023.
10. चक्रवर्ती, आर., और आर. अब्राहम. “The Impact of Financial Inclusion on Economic Development: The Mediating Roles of Gross Savings, Social Empowerment and Economic Empowerment.” *International Journal of Social Economics*, 2021.
11. केसी, एम., जे. सॉन्डर्स, और टी. ओ’हारा. “Impact of Critical Social Empowerment on Psychological Empowerment and Job Satisfaction in Nursing and Midwifery Settings.” *Journal of Nursing Management*, 2010.
12. लोगन, एम. एस., और डी. सी. गैंस्टर. “The Effects of Empowerment on Attitudes and Performance: The Role of Social Support and Empowerment Beliefs.” *Journal of Management Studies*, 2007.
13. नॉर्ड, जे. एच., आदि. “Examining the Impact of Social Technologies on Empowerment and Economic Development.” *International Journal of Information Management*, 2016.
14. पुहाज़ेन्धी, वी., और के. जे. एस. सत्यसाई. “Economic and Social Empowerment of Rural Poor through Self-Help Groups.” *Indian Journal of Agricultural Economics*, 2001.
15. चक्रवर्ती, आर., और आर. अब्राहम. “The Impact of Financial Inclusion on Economic Development: The Mediating Roles of Gross Savings, Social Empowerment and Economic Empowerment.” *International Journal of Social Economics*, 2021.

16. केसी, एम., जे. सॉन्डर्स, और टी. ओ'हारा. "Impact of Critical Social Empowerment on Psychological Empowerment and Job Satisfaction in Nursing and Midwifery Settings." *Journal of Nursing Management*, 2010.
17. कुग्लर, जे. *Political Capacity and Economic Behavior.* 2018.
18. पुहाज़ेन्धी, वी., और के. जे. एस. सत्यसाई. "Economic and Social Empowerment of Rural Poor through Self-Help Groups." *Indian Journal of Agricultural Economics*, 2001.
19. वू, एक्स., एम. हॉवलेट, और एम. रमेश. *Policy Capacity and Governance: Assessing Governmental Competences and Capabilities in Theory and Practice.* 2017.
20. मेनन, एस. टी. "Psychological Empowerment: Definition, Measurement, and Validation." *Canadian Journal of Behavioural Science*, 1999.
21. ओलादीपो, एस. ई. "Psychological Empowerment and Development." *Edo Journal of Counselling*, 2009.
22. स्प्राइट्ज़र, जी. एम. "Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation." *Academy of Management Journal*, 1995.
23. वाग्नर, जे. आई. जे., आदि. "The Relationship between Structural Empowerment and Psychological Empowerment for Nurses: A Systematic Review." *Journal of Nursing Management*, 2010.
24. ज़िम्मरमैन, एम. ए. "Psychological Empowerment: Issues and Illustrations." *American Journal of Community Psychology*, 1995.